विदेशी कंपनियों को दिए गए ठेके

62. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 1984 से आज तक विदेशी कंपनियों को कौन-कौन से ठेके दिये गये हैं तथा उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक ठेके की अलग-अलग धनराशि कितनी है और इन करारों पर किन-किन तारीखों को हस्ताक्षर किये गये ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग के लिए सरकार ने वर्ष 1984 और 1985 में क्रमशः 752 और 1024 प्रस्ताव अनुमोदित किये हैं । भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम उत्पादन की वस्तु और सहयोग की किस्म का उल्लेख करते हुए सभी विदेशी सहयोगों के ब्यौरे त्रैमासिक आधार पर भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूजलेटर" के एक पूरक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। संसद पुस्तकालय को इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से भेजी जाती हैं । नीति के अनुसार जनहित की दृष्टि से वित्तीय ब्यौरों की स्पष्ट जानकारी प्रकट नहीं की जाती ।

प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग

63. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**:
डा. बापू कालदाते :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री 17 मार्च, 1986 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2050 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि पाठ्यक्रम को राजभाषा के माध्यम से शिक्षण दे रहे 23 विश्वविद्यालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए ;

(ख) इसी अवधि के दौरान किन-किन राज्यों में न्यायिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कितने छात्रों ने अपने उत्तर हिन्दी में लिखे, और उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया ;

(ग) 19 सितम्बर, 1985 को प्रधान मंत्री द्वारा विज्ञान भवन में दिए गए अनुदेशों के बावजूद किन कारणों से उनके मंत्रालय ने अभी तक राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्यक्रम को अब तक पूरा नहीं किया है ;

(घ) 1985-86 के लिए राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यक्रम को किन कारणों से कार्यान्वित नहीं किया गया है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि वर्ष 1986-87 के लिए राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयवार हिन्दी में कितने निर्णय दिए गए ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) संबंधित विश्वविद्यालयों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) संबंधित राज्य लोक सेवा आयोगों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 343 में यथा उपबंधित संघ की राजभाषा हिन्दी है । राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर जोर दिया गया है और राजभाषा से संबंधित संविधान के भाग 17, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के और इस निमित्त राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग